संपादकीय

यूजीसी की अच्छी पहल

यूजीसी ने स्टूडेंट के लिए अलग-अलग डिसिप्लिन में पढ़ाई और अपने हुनर को निखारना का मौका देने के लिए दो विषयों में एकसाथ डिग्री लेने को मान्यता दी है। किन-किन विषयों में एक साथ दो डिग्रियां ली जा सकती हैं, यह अलग-अलग संस्थानों पर निर्भर करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे स्टूडेंट पर दबाब और नहीं बढ़ेगा।

जिन कॉलेजों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) और भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों की मान्यता है, उनसे अकादमिक सत्र 2022-23 से डिप्लोमा, अंडर ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट लेवल पर स्टूडेंट्स एक साथ दो विषयों में डिग्री ले सकते हैं। यूजीसी का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स की स्किल बेहतर होगी। दोनों डिग्रियां एक साथ क्लास में पढ़ाई, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन या दोनों ऑनलाइन तरीके से ली जा सकती हैं। यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसे अपनाने या नहीं अपनाने की आजादी यूनिवर्सिटी को दी गई है। किन-किन विषयों में एक साथ दो डिग्रियां ली जा सकती हैं, यह अलग-अलग संस्थानों पर निर्भर करेगा। इससे किसी स्टूडेंट को एक साथ साइंस और हिस्ट्री या साइंस में ही दो विषयों से डिग्री लेने की आजादी मिलेगी। कोई चाहे तो एक साथ बीकॉम और साइंस में भी डिग्री ले सकता है। अगर कोई एक ही यूनिवर्सिटी से दोनों विषयों की ऑफलाइन डिग्री की पढ़ाई कर रहा है तो यह देखना होगा कि उनके क्लास एक ही समय में ना हों। ऐसे में स्टूडेंट एक विषय की पढ़ाई मॉर्निंग और दूसरे की इवनिंग शिफ्ट में कर सकता है। यूजीसी की गाइडलाइंस इस मामले में दो संस्थानों से भी पढ़ाई करने की इजाजत देती है। लेकिन यह तभी मुफीद होगा, जब दोनों संस्थान आसपास हों। एक साथ दो डिग्री के लिए योग्यता की शर्तों और यूनिवर्सिटी के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूजीसी का कहना है कि यह पहल नई शिक्षा नीति के तहत की गई है। इसका मकसद अलग-अलग डिसिप्लिन में पढ़ाई का मौका देकर उनके हुनर को निखारना है। इससे ऐसे स्टूडेंट्स की रोजगार पाने की संभावना बेहतर होगी। लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी हैं। पहला तो यही है कि एक ही विषय से डिग्री लेने में अकादमिक दबाव कम नहीं होता। ऐसे में एक स्टूडेंट क्या दो विषयों से एक साथ डिग्री का प्रेशर सह पाएगा दूसरा सवाल शिक्षा के स्तर से जुड़ा हुआ है। कई कंपनियां, सर्वे में यह बात सामने आई है कि भारत में एक हद तक शिक्षित छात्रों में भी रोजगार पाने की योग्यता नहीं होती। इसलिए एक साथ दो डिग्री की पहल के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की भी पहल करनी होगी। एक और समस्या उच्च शिक्षा में घटती दिलचस्पी की भी है। यूजीसी और अन्य सरकारी एजेंसियों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ, देश की अधिक से अधिक यूनिवर्सिटीज अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अपनी जगह बना पाएं, इसके लिए कोशिशें और तेज करनी होंगी। यानी इस मामले में एक व्यापक सोच की जरूरत है, जिससे उच्च शिक्षा में देश का दर्जा बेहतर हो।

131वें जन्मोत्सव पर याद किए गए भारतीय संविधान के निर्माता

लुधियाना। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के कारण मिली देश की आजादी को संभालने और इसकी एकता-अखंडता को बरकरार रखने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन व खूबसूरत संविधान रचने वाले भारत रत्न, बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी के 131वें जन्मोत्सव पर समारोहों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हर समारोह में नौजवान वर्ग को बाबा साहिब की शिक्षाओं व पदचिन्हों पर चलने की अपील की गई। पेश है हमारे संपादक राजकुमार साथी की विस्तृत रिपोर्ट।

बाबा साहिब के बताए मार्ग पर चले नौजवान वर्ग : मलिक

लुधियाना। जिला प्रशसन की ओर से मिनी सचिवालय में मनाए गए समारोह के दौरान डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने कहा कि नौजवानों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। डीसी ने कहा कि डॉ. अंबेडकर महान विद्वान, न्यायकार, अर्थ शास्त्री, समाज सुधारक व राजनेता थे। गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद समाज के लिए दिए गए उनके योगदान की विश्व भर में सराहना होती है। भारत को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखकर देना उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। इस मौके पर एसडीएम वेस्ट जगदीप सहगल व सहायक कमिश्नर (जनरल) गुरबीर सिंह कोहली भी मौजूद रहे।

सभी वर्गों को न्याय व बराबरी दिलाना ही बाबा साहिब को सच्ची श्रद्धांजलि : भोला

लुधियाना। हलका पूर्वी के विधायक दलजीत सिंह भोला ग्रेवाल ने कहा कि समाज के हर वर्ग को न्याय व बराबरी दिलाकर ही भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। बाबा साहिब केवल कमजोर वर्ग के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के हितैषी थे। उन्होंने देश की आजादी के बाद भारत के नव निर्माण में अहम योगदान डाला। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना महान अर्थशास्त्री बाबा साहिब की सोच का ही परिणाम था। इस मौके प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर, संजीव कुमार संजू, सुरिंदर मदान, बादल प्रकाश, रोहित राजपूत, अश्वनी कुमार, गगन राय, दीपू मेहरा, वरुण कुमार, सुच्चा सिंह फंबड़ा, परमजीत पम्मी व गुरशरनदीप सिंह भी मौजूद रहे।

देश के हरेक नागरिक के लिए पूज्यनीय हैं बाबा साहिब डॉ. अंबेडकर

लुधियाना। भावाधस की ओर से मिनी सचिवालय में आयोजित समारोह के दौरान मुख्य संचालक वीरश्रेष्ठ नरेश धींगान ने कहा कि बाबा साहिब हर नागरिक के लिए पूज्यनीय हैं। उन्होंने हर वर्ग के लिए सामाजिक बराबरी व न्याय का मार्ग खोला है। उनकी ओर से रचे संविधान के कारण ही महिलाएं देश के शीर्ष पद तक पहुंची हैं। इस कारण उन्हें केवल दलितों का मसीहा कहने का अर्थ उनके कद को कम करना है। हर नागरिक को आज का यह दिन धूमधाम से मनाना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री (कार्यवाहक) वीरश्रेष्ठ राजकुमार साथी, यूथ विंग पंजाब के अध्यक्ष वीर नीरज सुबाहू, प्रांतीय सचिव वीर भोपाल सिंह पुहाल, जिला संयोजक वीर पिंका चंडालिया, शहरी अध्यक्ष वीर हैपी राहत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वीर सुभाष सौदे, शहरी सचिव वीर सुधीर बद्दोवाल, वीर विकास सौदे, वीर आकाश लोहट, वीर मोनू सिद्धू, वीर बिट्टू, वीर सोनू शर्मा, वीर संदीप चनालिया, वीर अक्षय कुमार समेत भावाधस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

आंबेडकर को भुनाया, सोच नहीं अपनाई

(मोहनदास नैमिशराय)

आंबेडकर कभी पराए थे, आज अपने हैं।
आंबेडकर कभी देशद्रोही थे, आज देशभक्त हैं।
आंबेडकर कभी हिंदू विरोधी थे, आज हिंदुत्व को बचाने वाले हैं।

ब्रिटिश भारत के पचास बरस। आजाद भारत के पचास बरस। कुल मिलाकर 100 वर्षों में डॉ. भीमराव आंबेडकर की स्थिति अलग-अलग रही। समाजशास्त्रियों से लेकर राजनीतिक गलियारों में उनके बारे में जो स्वर उभरे, उनमें उन्हें नकारा अधिक गया और स्वीकारा कम। सामाजिक न्याय पर आंबेडकर का जो चिंतन था, उसे लेकर सवर्णों के बीच द्वंद्व रहा। लेकिन नई शताब्दी आते-आते भारतीय राजनीति का रंग बदलने लगा। वक्त उनकी बंद खिड़कियों और दरवाजों पर दस्तक दे रहा था और परंपरागत समाज के भीतर परिवर्तन लाने की गुहार भी लगा रहा था।

गांधी या आंबेडकर

एक बार महात्मा गांधी ने कहा भी था, 'आंबेडकर अगर पत्थर भी मारें तो मैं सह लूंगा।' वैसे, एक सीमा तक गांधी और गांधीवादियों ने आंबेडकर को सहा भी। इस तरह से आंबेडकर को झेलने वाली सवर्ण नेताओं की जमात बड़ी हुई। इससे देश, समाज का भला ही हुआ। इस तरह आंबेडकर के सामाजिक दर्शन को फिर से पढ़ने और समझने का दौर शुरू हुआ। कुछ ने इतिहास से सबक लिया। कुछ ने अपनी राजनीति से आंबेडकर को जोड़कर नई संभावनाओं की तलाश की। जिन्हें सत्ता तक पहुंचने की चाह थी, उनके लिए तो आंबेडकर को फिर से स्थापित करना बेहद जरूरी था। राजनीति के इसी टर्निंग पॉइंट के कारण बाबा साहब स्थापित होते गए।शुरुआत में गांव-कस्बों से महानगर तक, पार्कों और चौराहों पर आंबेडकर की मूर्तियां लगाई गईं। स्कूल-कॉलेज के सिलेबस में बदलाव किए गए। आंबेडकर की जीवनी पढ़ाने का दौर शुरू हुआ। राज्यसभा में भी दलित प्रतिनिधियों का प्रवेश हुआ। विधानसभाओं से लेकर संसद तक में आंबेडकर को संविधान निर्माता से लेकर राष्ट्रनिर्माता कहने की प्रतिस्पर्धा अलग-अलग राजनीतिक दलों के मुखियाओं के बीच होने लगी। इस होड़ में गांधी पीछे छूटते गए, आंबेडकर आगे निकलते गए। कुछ राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व ऐसा चाहता भी था। ये वे लोग थे, जो आजादी के 40-50 वर्षों तक राजनीति के बाजार में गांधी के नाम को कैश करते आए थे। आखिर ये लोग कब तक गांधी का नाम लेते

कांग्रेस ने आंबेडकर को अपनी राजनीति से जोड़ने में जितनी देरी की, उतनी ही तेजी बीजेपी ने दिखाई। इसे जनपथ पर आंबेडकर प्रतिष्ठान और 26 अलीपुर रोड, दिल्ली पर बाबा साहब डॉ. आंबेडकर संग्रहालय से समझा जा सकता है। कांग्रेस ने इनके लिए योजना बहुत पहले बनानी शुरू कर दी थीं, लेकिन अमल में काफी देरी हुई। वैसे, 90 के दशक में वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने आंबेडकर जन्म शताब्दी समारोह मनाया। इसी संदर्भ में यह बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र सरकार ने आंबेडकर की पांडुलिपियों और भाषणों को 'बाबा साहब डॉ. आंबेडकर संपूर्ण वाडमय' के नाम से प्रकाशित कराना भी शुरू किया। फिर शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने औरंगाबाद में बाबा साहब डॉ. आंबेडकर विश्वविद्यालय की घोषणा की।कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने आंबेडकर को ज्यादा तरजीह नहीं दी, जबकि केरल, पश्चिम बंगाल के साथ अन्य प्रदेशों में भी उनकी कई बार सरकारें बनीं। कम्युनिस्ट नेताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जाति से अधिक वर्ग को अहमियत देते थे। यह बात और है कि इन राज्यों में दलितों के वोट से वे सरकार बनाते रहे।जहां तक बीएसपी की बात है, सत्ता में आने के लिए कांशीराम और मायावती ने न केवल आंबेडकर को पूरी तरह से स्थापित किया बल्कि दलित वोटरों को जागरूक करने में भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। इससे यूपी में बीएसपी को कई बार सत्ता मिली। लेकिन आम दलितों को उनकी सरकार में क्या मिला, यह शोध का विषय है।अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर आते हैं। मानसिक रूप से सवर्ण नेता जब बाबा साहब का नाम लेते हैं तो दलितों के भीतर नई उम्मीदें जगती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके लिए समृद्धि के रास्ते खुलेंगे, उन्हें न्याय मिलेगा। दूसरे सवर्ण नेता सोचते हैं कि वे सबके लिए तो खुशहाली के दरवाजे खोल नहीं सकते, इसलिए वैसा कुछ किया जाए, जिससे दलित प्रभावित हों। केजरीवाल से दलित प्रभावित हुए भी। 'झाड़ू' चुनाव चिह्न रखना उनकी दूरदर्शिता थी। आप सरकार में सफाईकर्मियों को कितना कुछ मिला, यह तो वे ही जानें, लेकिन इतना जरूर है कि आप ने दलित वोटरों को आकर्षित किया। दिल्ली में वह फिर से सत्ता में आई। यहां तक कि दलितों ने बीएसपी को भी नकार दिया। जहां तक आंबेडकर की तस्वीरें सरकारी दफ्तरों में लगवाने की घोषणा का सवाल है तो यह घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की है।लेकिन दलितों की शिक्षा, रोजगार के अवसर और उनके जीवनस्तर में बड़े बदलाव को लेकर गंभीरता से कम सोचा गया और अगर सोचा भी गया तो ईमानदारी से उस पर अमल नहीं हुआ। आजादी से अब तक हुए तमाम चुनावों को देखते हुए वोटर इतना तो समझ ही गए हैं कि हर चुनाव के बाद सामाजिक न्याय की धारा तो साल या छह माह ही बढ़ पाती होगी, अगले चार वर्षों में तो जनता के प्रतिनिधियों पर कॉरपोरेट हावी हो जाते हैं या सरकारें कॉरपोरेट अंदाज में काम शुरू कर देती हैं।

यूपी- नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए स्वतंत्र देव सिंह की विरासत संभालना आसान नहीं

12 अप्रैल की सुबह आए यूपी विधानपरिषद चुनाव के नतीजों में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें हैरानी का कोई तत्व रहा हो। इस बात का पूर्वानुमान लगभग एमएलसी चुनाव की घोषणा के साथ ही हो गया था कि भाजपा को टक्कर देने वाला कोई और दल यूपी में कम से कम फिलहाल तो नहीं है। 36 में से 33 एमएलसी जीतकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा समेत विधानपरिषद में भी ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर लिया है।

(विवेक शुक्ला)

12 अप्रैल की सुबह आए यूपी विधानपरिषद चुनाव के नतीजों में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें हैरानी का कोई तत्व रहा हो। इस बात का पूर्वानुमान लगभग एमएलसी चुनाव की घोषणा के साथ ही हो गया था कि भाजपा को टक्कर देने वाला कोई और दल यूपी में कम से कम फिलहाल तो नहीं है। 36 में से 33 एमएलसी जीतकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा समेत विधानपरिषद में भी ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर लिया है। 40 साल में ये पहली बार है जब यूपी विधान परिषद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। और भाजपा ने तो ये रिकॉर्ड प्रदर्शन पहली बार कर दिखाया है। इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। यूपी विधान परिषद में 100 सीटें हैं जिनमें से 67 पर अब भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज लहरा रहा है।विधानसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का ऐतिहासिक करनामा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर ही चुके हैं। 16 जुलाई 2019 को अध्यक्ष पद संभालने से लेकर अब तक ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचा चुके स्वतंत्र देव सिंह का विकल्प ढूंढ़ने की ज़ोर शोर से कवायद की जा रही है। ऐसे में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के अब तक के तमाम प्रदेश अध्यक्षों में सबसे उल्लेखनीय कार्यकाल वाले अध्यक्षों में से रहे हैं

चाहे 2019 के आमचुनाव रहे हों, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह परिवहन मंत्री रहते हुए मप्र के चुनाव प्रभारी थे और 29 में से 28 सीटें जीती थीं या फिर 2020 के यूपी उपचुनाव रहे हों जिसमें सिंह ने पार्टी का नेतृत्व अध्यक्ष के तौर पर किया था और कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच भाजपा ने 7 में से 6 सीटें जीती थीं। या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हों जिनमें भाजपा ने ऐतिहासिक जनादेश पाकर दोबारा हिंदी हृदय प्रदेश में सरकार बनाई।

स्वतंत्र देव सिंह के निकट के लोग बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत गैर-विवादित छवि, कार्यकर्ताओं से उनका व्यक्तिगत संबंध और सदैव जमीन से जुड़े रहना है। पार्टी अध्यक्ष के पास सरकार जैसी ताकत नहीं होती ऐसे में संगठनकर्ता का अपना व्यक्तिगत व्यवहार उस कमी की पूर्ति करता है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए स्वतंत्र देव सिंह सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। उनकी समस्याएं सुनकर और सरकार तक उसे पहुंचा कर पार्टी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच एक मजबूत पुल का निर्माण उन्होंने किया है जिसका परिणाम चुनावों में एक के बाद एक सफलता के रूप में देखा जा रहा है।अपनी व्यावहारिक और सादा जीवन शैली की वजह से स्वतंत्र देव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की पसंद भी हैं और दिल्ली से भी उनकी प्रभावी जुगलबंदी है। राजनीति में अपराजेय एक जोखिम भरा विशेषण है लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की मजबूत स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि फिलहाल के लिए तो पार्टी इस विशेषण की हकदार है।

ऐसे प्रदर्शन के मद्देनजर यूपी भाजपा के लिए आने वाला अध्यक्ष ढूंढ़ना और नए अध्यक्ष के लिए जिम्मेदारियों का उसी तत्परता से निर्वहन कर पाना आसान नहीं लगता। कयासों की बात करें तो दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा का नाम फिलहाल दावेदारी में आगे चल रहा है। प्रदेश में भाजपा अध्यक्षों का 2004 से लेकर 2019 तक का पैटर्न देखें तो लगता है कि पार्टी ब्राह्मण समुदाय से ही किसी नेता को अध्यक्ष नियुक्त करेगी। 2004 से लेकर अब भाजपा ने ओबीसी के बाद ब्राम्हण और फिर से ओबीसी अध्यक्ष का ही पैटर्न रखा है। श्रीकांत शर्मा को तो दो हफ्ते पहले कई ब्लू-टिक धारी पार्टी पदाधिकारियों से नए अध्यक्ष पद की बधाई तक दे दी थी हांलाकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अध्यक्ष की पगड़ी किसके सिर धरी जाएगी। बहरहाल, नया अध्यक्ष चाहे जो भी हो, उसके लिए स्वतंत्र देव सिंह की विरासत को उतनी ही ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना खासा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। (वरिष्ठ पत्रकार स्वतंत्र राजनीतिक टिप्पणीकार हैं)ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

भगवंत मान की द हाफ सीएम वाली छवि केजरीवाल ने पुख्ता कर दी है

हाल ही में पंजाब में पांच सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनावों में भी जिस तरह से सदस्यों की घोषणा हुई उसमें भी सन्देह पैदा होने लगा है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई की कम और हाईकमान की ज्यादा चली है।पंजाब में सत्ता परिवर्तन के उपरान्त नौकरशाहों के दिल्ली चक्कर पर यहां के प्रशासनिक क्षेत्र में मुख्यमन्त्री भगवन्त मान को अन्दरखाते 'दि हाफ सीएम' के नाम से पुकारा जाने लगा है परन्तु हाल ही के ताजा घटनाक्रम ने मान के इस नए नामकरण पर स्वीकृति की भी मुहर लगा दी लगती है।

(राकेश सैन)

हाल ही में पंजाब में पांच सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनावों में भी जिस तरह से सदस्यों की घोषणा हुई उसमें भी सन्देह पैदा होने लगा है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई की कम और हाईकमान की ज्यादा चली है।पंजाब में सत्ता परिवर्तन के उपरान्त नौकरशाहों के दिल्ली चक्कर पर यहां के प्रशासनिक क्षेत्र में मुख्यमन्त्री भगवन्त मान को अन्दरखाते 'दि हाफ सीएम' के नाम से पुकारा जाने लगा है परन्तु हाल ही के ताजा घटनाक्रम ने मान के इस नए नामकरण पर स्वीकृति की भी मुहर लगा दी लगती है। मामला यह है कि भगवन्त मान और बिजली मन्त्री हरभजन सिंह की अनुपस्थिति में पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, बिजली विभाग के सचिव दलीप कुमार, ऊर्जा निगम (पावरकॉम) के मुख्य प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) बलदेव सिंह सरां ने दिल्ली के मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, वहां के मन्त्री सत्येन्द्र जैन और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के साथ बैठक की। आम आदमी पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने सम्बन्धी वायदा किया गया था, अब जबकि पंजाब में पार्टी की सरकार बन चुकी है, ऐसे में लोगों ने निःशुल्क बिजली की मांग शुरू कर दी है। इसी को लेकर केजरीवाल ने पंजाब के उक्त अधिकारियों की बैठक बुलाई। चाहे केजरीवाल सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं परन्तु पंजाब में चुनी गई सरकार वैधानिक सीमा में बन्धी है। राज्य के संवैधानिक मुखिया या उनके चुने हुए प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में इस तरह की बैठक पूरी तरह से अवैध, राज्य के मामलों में हस्तक्षेप और देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। पंजाब में सत्ता के तार दिल्ली से झनझनाने की दुर्गंध तो नई सरकार के कार्यभार सम्भालने के बाद से ही आनी लगी थी। अमृतसर (उत्तर क्षेत्र) से विधायक व पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह अपनी ही सरकार की स्थानान्तर व नियुक्ति सम्बन्धी नीति पर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने दो वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों प्रबोध कुमार को विशेष डीजीपी (गुप्तचर) और अरुणपाल सिंह को अमृतसर का पुलिस आयुक्त नियुक्त करने का विरोध किया। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपना विरोध जाताया। चाहे बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को बदल दिया परन्तु तब तक मीडिया की सुर्खियां बनने पर मान सरकार की जगहंसाई हो चुकी थी। कुंवर विजय प्रताप का आरोप है कि बेअदबी काण्ड में अप्रैल 2021 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल द्वारा की गई एक जांच को रद्द कर दिया था। कुंवर विजय प्रताप भी इसका हिस्सा थे। यह दल 2015 में कोटकपुरा और बहिबलकलां में गुरु ग्रन्थ साहिब की बेअदबी का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग के 2 मामलों की जांच कर रहा था।न्यायालय के आदेश के बाद कुंवर विजय प्रताप नौकरी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में आगए। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त दोनों अधिकारी बड़े राजनीतिक परिवारों के पक्षधर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बरगाड़ी-बहबलकलां मामले में न्याय न मिलने के लिए ये दोनों अधिकारी जिम्मेदार हैं। चाहे मुख्यमन्त्री मान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी परन्तु इससे संकेत तो मिले हैं कि पंजाब की क्रान्तिकारी सरकार में कुछ गड़बड़झाला तो है। सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस सरकार के चहेते अधिकारी आज आप की सरकार में किस तरह अपनी पसन्द के पद हासिल कर रहे हैं दूसरी तरफ हाल ही में पंजाब में पांच सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनावों में भी जिस तरह से सदस्यों की घोषणा हुई उसमें भी सन्देह पैदा होने लगा है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई की कम और हाईकमान की ज्यादा चली है। 'आप' ने जालन्धर के रहने वाले क्रिकेटर हरभजन सिंह, फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति अशोक मित्तल, पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा, लुधियाना से उद्योगपति संजीव अरोड़ा और दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर डॉ. सन्दीप पाठक को राज्यसभा भेजा है। पार्टी पर केवल विपक्ष ने ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर उसके कार्यकर्ताओं ने ही आरोप लगाया कि यह नाम राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। इन नामों के चुनाव में हाईकमान संस्कृति पंजाब के मुख्यमन्त्री पर भारी नजर आई।

वैसे विधानसभा चुनावों के दौरान भी 'आप' के राजनीतिक विरोधियों ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल अपरोक्ष रूप से पंजाब की राजनीति व प्रशासन पर नियन्त्रण चाहते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती और पश्चिम बंगाल की मुख्यमन्त्री एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी की भांति केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के अघोषित एकछत्र सर्वेसर्वा हैं। उनके साथ उसी नेता की दाल गल सकती है जो 'हाफ टिकेट' सीट पर बैठने को तैयार हो। आम आदमी पार्टी का संक्षिप्त इतिहास भी साक्षी है कि चाहे योगेन्द्र यादव हों या कुमार विश्वास, किरण बेदी, आशुतोष व अन्य नेता, किसी ने भी फुल टिकेट की चाह रखी तो केजरीवाल ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया।पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के चलते अरविन्द केजरीवाल को पूरा अधिकार है कि वह अपनी पार्टी की सरकार पर कड़ी नजर रखें और उसका मार्गदर्शन करें परन्तु संविधान के दायरे में रह कर। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी राष्ट्रीय नेता ने अपने सत्ताधारी राज्य के संवैधानिक मुखिया या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में उसके अधिकारियों के साथ बैठक की हो। मुख्यमन्त्री मान को साहस कर अपने अधिकारियों से इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर वे किस के आदेश से बैठक में गए। देश दस सालों तक एक कठपुतली प्रधानमन्त्री को झेल चुका है और उसी मार्ग पर भगवन्त मान चलते हैं तो यह पंजाब की जनता के जनादेश का घोर अपमान होगा। पंजाब की जनता उन्हें पूर्णरूपेण मुख्यमन्त्री के रूप में देखना चाहती है न कि 'दि हाफ सीएम' के रूप में।